

वर्धा शिक्षा नीति (1937)

Waridha Education Policy

महात्मा गाँधी ने अपने 'शैक्षिक विचारों पर जुली बरस' करने के उद्देश्य से '23 अक्टूबर 1937' को वर्धा में 'शांति आरक्षणीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन' किया। इसमें देश के साहित्यकारों, 'शिक्षा मर्मियों', 'समाज सुधारकों' और 'राष्ट्रीय नेताओं' ने भाग लिया।

इस सम्मेलन को ही 'वर्धा शिक्षा सम्मेलन' कहा जाता है। इस योजना पर विचार-विमर्श के अग्रलिखित सुझाव/या संस्तुतियाँ प्रस्तुत की थी।

- ⇒ 7 वर्ष आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाये।
- ⇒ शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।
- ⇒ बच्चों को शिल्प-कौशल को कौशल सिखाने की व्यवस्था की जाये।
- ⇒ बच्चों को हस्त-शिल्प शिक्षा उनके वातावरण से सम्बन्धित होनी चाहिए।

'डॉ. जाकिर हुसैन' की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी, जिसने इस प्रणाली को कार्यक्रम में परिचित करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्तुत किया -

- 1- प्रथम प्रतिवेदन - (First Report) यह प्रतिवेदन दिसम्बर सन् 1937 में प्रस्तुत किया गया। इसके अन्तर्गत शिक्षा योजनाओं के सिद्धान्तों, उद्देश्यों, शिक्षण, विद्यालय, संगठन, प्रशासन, निरीक्षण, हस्त-शिल्प जैसी पाठ्यक्रम व्यवस्थाओं का निर्णय लिया गया।
- 2- द्वितीय प्रतिवेदन - इसके अन्तर्गत हस्त-शिल्प सम्बन्धी व्यापक पाठ्यक्रम तैयार किया गया। जिसमें मिट्टी का नर्च, कर्ताई-बुनाई, लकड़ी का कार्य, कागज एवं रस्ते का कार्य आदि के महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया।

यह रिपोर्ट सन् 1938 में प्रस्तुत की गयी।
इसे बुनियादी शिक्षा, नई तालीम, बेसिक शिक्षा, वर्षा योजना
आदि नामों से पुकारा गया।